पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 923/2018

चंदन थाना कांड संख्या-43/2012 जिला-बांका से उत्पन्न

=====

1. मोहिनी देवी, पति देव नारायण यादव
2. सचिंद्र यादव, पिता देव नारायण यादव दोनों निवासी-गाँव-केंदुआर, थाना चंदन (आनंदपुर), जिला-बांका

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदातागण

=====

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं की ओर से : श्री अजय मुखर्जी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं की ओर से : श्री अभिमन्यु शर्मा, अपर लोक अभियोजक

=====

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 374(2) के अंतर्गत अपील - दहेज हत्या के लिए दोषसिद्धि - गवाहों (जैसे, पड़ोसियों) की गवाही में विरोधाभास और घटनाओं की समय-सीमा में असंगतता ने मृतक की मृत्यु के लिए सटीक परिस्थितियों के बारे में संदेह पैदा किया। - हालांकि, पीड़ित की मृत्यु के लिए दहेज-संबंधी क्रूरता की निकटता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत अनुमान लगाया, जिसका बचाव पक्ष पर्याप्त रूप से खंडन करने में विफल रहा। माना गया कि धारा 304-बी/34 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया और अपीलकर्ताओं की आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की गई।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक: 25-06-2024

हमने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय मुखर्जी और राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अभिमन्यु शर्मा को सुना।

2. अपीलार्थी, जो मृतक की सास और पति हैं, का विद्वान एफ. टी. सी.-I, बांका द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पारित फैसले के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसी तारीख के आदेश से, उसे आजीवन कारावास से गुजरने की सजा सुनाई गई।

3. मृतक की माँ राधिया देवी (अभियोजन साक्षी-6) ने 23.04.2012 का *फरदबयान* दर्ज कराया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी/मृतका की शादी तीन साल पहले अपीलार्थी संख्या- 2 से हुई थी। हालाँकि, उसके खराब दिखने और पर्याप्त दहेज न लाने के कारण उसके वैवाहिक घर में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। उसे प्रताड़ित किया गया और अपीलार्थी संख्या-2 द्वारा धमकी दी गई कि किसी अन्य व्यक्ति से पुनर्विवाह कर लिया जाएगा। दिनांक 23.04.2012 को, अपीलार्थी संख्या -2 ने मृतक की माँ/अभियोजन साक्षी-6 को सूचित किया कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई है और उसे और परिवार के सदस्यों को तुरंत आना चाहिए। ऐसी सूचना पर, वह कमली देवी, शकुंतला देवी, नरेश यादव और चतुरगुन यादव के साथ मृतक के ससुराल गई और उसे एक खाट पर मृत

पाया। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि अपीलकर्ताओं ने मृतक की हत्या कर दी थी और वे ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे थे ताकि यह आत्म-हत्या का मामला समझा जा सके।

4. अभियोजन साक्षी-6 के पूर्व उल्लिखित *फरदबयान* बयान के आधार पर, आई. पी. सी. की धारा 341,323,304-बी, 504,506 और 34 के तहत अपराधों की अनुसंधान के लिए चंदन (आनंदपुर) थाना कांड संख्या- 43/2012 दिनांक 23-04-2012 का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर संज्ञान लिया गया और मामला सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

5. विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों से परीक्षण करने के बाद अपीलार्थियों को उपरोक्त के अनुसार दोषी ठहराया।

6. यहां यह बताना प्रासंगिक हो सकता है कि अभियोजन साक्षी-6 द्वारा मृतक के वैवाहिक घर जाने पर जिन व्यक्तियों का नाम लिया गया था, उनमें से केवल चतुरगुन यादव (अभियोजन साक्षी-4) की परीक्षण की गई थी। बाकी अन्य सभी को अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रूप में खड़ा नहीं किया गया था।

7. पप्पु यादव (अभियोजन साक्षी-1) केवल जाँच रिपोर्ट (प्रदर्श-1) के हस्ताक्षरकर्ता हैं और उन्होंने घटना के कारण के बारे में पूर्ण अज्ञानता व्यक्त किया है।

8. अभियोजन साक्षी- 2,3 और 5, अर्थात रामानंद प्रसाद भगत, कुलदिप प्रसाद यादव और महादेव यादव को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था।

9. चतुरगुन यादव (अभियोजन साक्षी -4), जो मृतक के चाचा हैं, ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है, लेकिन उनके साक्ष्य में सामग्री विवरण का अभाव है जो अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करने में मदद कर सकता है। उन्होंने दोहराया है कि दिनांक 23.04.2012 को लगभग 6:00 बजे सुबह, अपीलार्थी संख्या- 2 ने

उन्हें टेलीफोन पर सूचित किया कि मृतक की मृत्यु हो गई है। वह कमली देवी, शकुंतला देवी, राधिया देवी (अभियोजन साक्षी -6) और अन्य लोगों के साथ मृतक के वैवाहिक घर गए और उसे मृत पाया। वह एक खाट पर लेटी हुई थी। घर में कोई नहीं था। ग्रामीणों ने उसे बताया कि अपीलकर्ता संख्या- 2 ने मृतक को पीटने की कोशिश की थी, जबकि अपीलकर्ता संख्या 1 (सास) ने उसे जहर दिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि मृतक ने फांसी लगा ली थी। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने मृतक को लटकते हुए देखा था।

10. यह स्पष्ट रूप से एक गलत बयान है क्योंकि उन्होंने बयान के पहले भाग में कहा है कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर मृतक को खाट पर लेटे हुए देखा था। अपीलार्थियों द्वारा मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। उन्होंने दावा किया है कि 15-20 मिनटों के भीतर, कई लोग मृतक के वैवाहिक घर में आ गए। उनके साथ अन्य ग्रामीण भी थे जालंधर यादव, सिकंदर यादव, भिखारी यादव, सहदेव यादव, महादेव यादव, बरसाती यादव और शिव लखन यादव। विचारण में उनमें से किसी की भी परीक्षण नहीं की गई है। उसकी भतीजी (मृतक) हमेशा उसे बताती थी कि मोटरसाइकिल की लगातार मांग थी। हालाँकि, उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी। पूछताछ किए जाने पर उन्होंने दोहराया कि उन्होंने शव को लटका हुआ देखा था।

11. बहुत दिलचस्प बात यह है कि मृतक की माँ राधिया देवी (अभियोजन साक्षी-6), जो मामले की सूचक भी है ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और केवल यह कहा है कि मृतक अपने माता-पिता के घर आती थी, लेकिन उसने कभी भी दहेज या मोटरसाइकिल की मांग या अपने पति और सास के हाथों किसी भी बुरे व्यवहार के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। उसे इस बात का पता नहीं था कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई। पुलिस द्वारा उसके सामने जो भी दस्तावेज लाया गया था, उस पर उसके हस्ताक्षर थे। दूसरों के पूछने पर, कहा जाता है कि उसने तत्काल मामला दर्ज कराया था।

12. मृतक के शव का 23.04.2012 को लगभग 4:30 बजे "शाम में पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर को पता चला कि नाक से अंदर का भाग निकल रहा है। गर्दन क्षेत्र में आगे से पीछे तक बंधन का निशान था। आंतरिक रूप से, त्वचीय ऊतक क्षतिग्रस्त हो गए थे और श्वासनली गुहा में, रक्त के थक्के मौजूद थे। एफएसएल से विसरा की रिपोर्ट आने तक राय सुरक्षित रखी गई थी।

13. जिस डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम किया, अर्थात डॉ. शैलेंद्र कुमार (अभियोजन साक्षी -7) के पास स्पष्ट रूप से एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, विसरा में कोई धातु, एल्कोइडल, ग्लाइकोसाइडल या कीटनाशक जहर नहीं पाया जा सका।

14. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने पुष्टि की है कि फांसी के मामले में, बंधन का निशान नियमित नहीं है।

15. अनुसंधान अधिकारी, अर्थात मो. जफिरुद्दीन खान (अभियोजन साक्षी -8) ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो अपराध में अपीलार्थियों की संलिप्तता के संबंध में मामले को तय करने में सहायक हो। उन्होंने आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, उनके पास विचारण न्यायालय को देने के लिए कुछ नहीं था।

16. शादी के सात साल के भीतर मृतक की अपने वैवाहिक घर में मृत्यु हो गई। अतीत में मोटरसाइकिल की मांग या दुर्व्यवहार की कोई शिकायत नहीं थी। मृतक की माँ (अभियोजन साक्षी -6) द्वारा *फरदबयान* में यह भी इंगित करता है कि शायद मृतक देखने में अच्छी नहीं थी और इसलिए, उसके पति उसे पसंद नहीं करते थे।

17. यह बयान पहली बार आया था जब मृतक की मृत्यु हो गई थी। इस तरह की कोई पूर्व शिकायत नहीं थी।

18. हमने पाया है कि मुकदमे के दौरान, अभियोजन साक्षी -6 ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे जिसे पुलिस द्वारा उसके सामने प्रस्तुत किया गया था। यह मामला अन्य लोगों के कहने पर भी दर्ज किया गया था। उनकी

बेटी ने कभी भी किसी भी बुरे व्यवहार की शिकायत नहीं की। अभियोजन साक्षी -6 को भी पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है।

19. इस प्रकार, अपीलार्थियों के खिलाफ एकमात्र सामग्री अभियोजन साक्षी -4 का बयान है। चतुरगुन यादव जिन्होंने मुकदमे के समक्ष विरोधाभासी बयान दिए हैं। एक समय पर, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने मृतक को खाट पर लेटे हुए देखा था, जबकि अदालत के समक्ष अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मृतक को छत से लटका हुआ पाया था। उन्हें यह भी पता चला था कि शायद मृतक को जहर देकर मार दिया गया था। हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि लिगेचर का निशान लटकने के कारण था जो गला घोटने के मामलों में संभव है।

20. हमने आरोप की प्रकृति के साथ-साथ इस बात को भी ध्यान में रखते हुए मामले का परीक्षण करने का प्रयास किया है और मृत्यु शादी के सात साल के भीतर हुई थी और मृत शरीर अपीलार्थियों के घर में पाया गया था।

21. यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन साक्षी -6 और अभियोजन साक्षी -4 दोनों ने पुष्टि की है कि मृत्यु के बारे में जानकारी अपीलार्थी संख्या -2 द्वारा दी गई थी। यह इस तथ्य का एक संकेत है कि अपीलार्थी किसी गुप्तता के तहत कार्य नहीं कर रहे थे या "शव को ठिकाने लगाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, यह दिखावा करने का भी प्रयास नहीं कर रहे थे कि कि मृतक फांसी लगाने का नाटक करने की कोशिश कर रहे थे।

22. दूसरा सवाल, जो हमारे मन में उठा है, वह यह है कि क्या आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि टिकाऊ होगी। आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए निम्नलिखित तत्व होने चाहिए:-

(i) एक महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो।

(ii) ऐसी मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई होनी चाहिए थी।

(iii) उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा होगा।

(iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

(v) इस तरह की क्रूरता या उत्पीड़न महिला के साथ "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" किया गया था।

23. बंसीलाल बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 11 एस. सी. सी. 359 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया कि आई. पी. सी. की धारा 304-बी के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, अपराध के मुख्य घटकों में से एक, जिसे स्थापित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले", उसे दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी मृत्यु के आवश्यक तत्व स्थापित किए जाते हैं, तो यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह यह अनुमान लगाए कि अभियुक्त दहेज मृत्यु का कारण बना है। यह भी देखा गया कि "उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले" अभिव्यक्ति को किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, प्रत्येक मामले में, न्यायालय को पीड़ित की मृत्यु के लिए तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करना होता है और यह तय करना होता है कि क्या दहेज की मांग और क्रूरता या उत्पीड़न और मृत्यु के कार्य के बीच कोई निकट संबंध है या नहीं।

24. शेर सिंह उर्फ प्रताप बनाम हरियाणा राज्य, (2015) 3 एस. सी. सी. 724 मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह दोहराया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और आई. पी. सी. की धारा 304-बी को उनके संबंधित कानूनों में एक साथ पेश किया गया था और इसलिए, यह सामान्य रूप से माना जाना चाहिए कि संसद ने जानबूझकर धारा 304-

बी में "मानित" शब्द का उपयोग किया था ताकि इस प्रावधान को वास्तविक में दूसरों से अलग किया जा सके। इन प्रावधानों के लिए स्वीकार्य अर्थ, जब तक कि "दिखाया गया" शब्द का उपयोग "साबित" के पर्याय के रूप में नहीं किया जाता है और "माना" शब्द का उपयोग "समझा गया" शब्द के साथ स्वतंत्र रूप से विनिमेय के रूप में किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि नागरिक और वित्तीय कानूनों के क्षेत्र में, "डीम" शब्द के सामान्य अर्थ को उन परिस्थितियों के एक समूह को दर्शाने के लिए आयात करना मुश्किल नहीं है जो वास्तव में हैं उसके विपरीत माने जाते हैं। हालाँकि, आपराधिक कानून में, इस दृष्टिकोण को अपनाना अनुचित है।

25. आम तौर पर यह माना जाता है कि खंडनीय और अखंडनीय दोनों तरह की धारणाएँ होती हैं जो एक मानित प्रावधान के माध्यम से वास्तविकता के रूप में एक कृत्रिमता मानते हैं। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराना आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए घृणित है, भले ही उसका न तो इसे करने का इरादा था और न ही उसके योजना में कोई सक्रिय भागीदारी थी। यह गहन विचार के बाद आई. पी. सी. की धारा 304-बी में "दिखाए गए" शब्द का अर्थ वास्तव में "साबित" करना है। दूसरे शब्दों में, यह साबित करना अभियोजन पक्ष का काम है कि "दहेज मृत्यु" हुई है:

- (i) असामान्य परिस्थितियों में, जलाना या महिला को शारीरिक चोट पहुँचाना,
- (ii) विवाह के सात वर्षों के भीतर,
- (iii) उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था।
- (iv) दहेज की किसी भी मांग के संबंध में, और
- (v) उसके साथ की गई क्रूरता या उत्पीड़न का दहेज की मांग के साथ कारणात्मक संबंध या एक जीवित संबंध बना रहा।

26. हमें यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है कि मृतक को दहेज की मांग के कारण से संबंध या दहेज की मांग के साथ एक लाइव लिंक के संबंध में किसी भी क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विवाह के सात वर्षों के भीतर असाधारण/असामान्य परिस्थितियों में मृतक की मृत्यु हो गई। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अगर ऐसा है तो इस तरह की हत्या घर की चार दीवारों के भीतर होती है, घटना के बहुत सारे गवाह नहीं होंगे, लेकिन फिर अभियोजन पक्ष को अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय द्वारा पूर्वधारणा को लागू करने के लिए बुनियादी तत्वों को साबित करनी होगी।

27. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, यह प्रावधान करती है कि जब यह प्रश्न आता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या का कारण बना था।

28. इस तरह की धारणा के प्रभावी होने के लिए, अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य तथ्यों को साबित करना होगा।

29. हमने अभिलेख पर साक्ष्य से पाया है कि किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई थी और जिन लोगों से पूछताछ की गई है, उन्होंने मृतक की मां सहित अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

30. मृतक के चाचा (अभियोजन साक्षी-4) ने विरोधाभासी बयान दिए हैं। इस बात का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मृतक के साथ कोई पूर्व क्रूरता की गई थी। किसी भी स्तर पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था या कोई शिकायत नहीं की

गई थी। केवल इसलिए कि मृतक अपीलार्थियों के घर में मृत पाया गया था, अभियोजन पक्ष इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि मृतक की हत्या दहेज के लिए की गई थी।

31. हमारे मन में एकमात्र संदेह मृतक के व्यक्ति पर बंधन चिह्न की प्रकृति है। यह गला घोटने के कारण भी हो सकता है; लेकिन फिर अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना होगा। यदि ऐसा होता तो अपीलार्थी संख्या- 2 ने मृतक की मृत्यु हो जाने के बाद अभियोजन साक्षी-4 को तुरंत अपने घर पर आने के लिए टेलीफोन से सूचना नहीं देता ।

32. इसके अलावा, अभियोजन साक्षी -4 का विरोधाभासी बयान से यह साबित होता है कि शायद दूसरों के कहने पर ही मामला दर्ज किया गया था तथा किसी भी तरह के जहर का कोई सबूत नहीं था ।

33. अन्वेषक (अभियोजन साक्षी -8) के बयान ने विचारण न्यायालय को कोई मदद नहीं दी है।

34. उपर्युक्त कारणों से, हमारे पास अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

35. इसलिए दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को निरस्त किया जाता है।

36. दोनों अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाता है।

37. अपीलार्थी नं. -1 जमानत पर है। उसे अपने जमानत बांड के तहत अपनी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

38. जेल में अपीलार्थी संख्या- 2 यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित या हिरासत में नहीं है तो उसे तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

39. अपील स्वीकृत की जाती है।

40. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन और अभिलेख हेतु संबंधित जेल के अधीक्षक को अविलंब भेजी जाए।

41. इस मामले के अभिलेखों को अविलंब विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

42. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा कर दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

राजेश/सौरव

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।